मेघराज कोठारी

बनाम

परिसीमन आयोग और अन्य

20 सितंबर, 1966

[के. सुब्बा राव, सी. जे., एम. हिदायतुल्ला, एस. एम. सिकरी, जे. एम. शीलत और जी. के. मित्तर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 82, 327, 328 और 329, परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9 के तहत आदेश, धारा 10(1) के तहत प्रकाशित-अनुच्छेद 327 के तहत कानून है- इसलिए क्या अदालत में सवाल उठाया जा सकता है या क्या अनुच्छेद 329 लागू होता है .

परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962, धारा 8, 9 और 10 - का दायरा।

परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 की धारा 10(1) के संदर्भ में जारी परिसीमन आयोग की दिनांक 24 जुलाई 1964 की एक अधिसूचना द्वारा, उज्जैन शहर, जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था, को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अपीलकर्ता जो कि उज्जैन का निवासी था और भारत का नागरिक था, ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें इस आधार पर अधिसूचना को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट की प्रार्थना की गई कि उसे उज्जैन शहर निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार है जो छीन लिया गया. याचिका को उच्च न्यायालय ने इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया कि अधिसूचना पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 329 (ए) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाए गए या बनाए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित अधिसूचना, जो धारा 9 के तहत एक आदेश था और अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया था, के अर्थ में एक कानून नहीं था। धारा 329; धारा 10(2) के तहत किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश कानून का बल होना चाहिए था लेकिन वह स्वयं एक कानून नहीं था; और यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 82 के तहत बनाई गई थी।

निर्धारण: अपील को खारिज करते हुए,

विवादित अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित एक कानून था।

अधिनियम की उपधारा 8 और 9 की जांच से पता चला कि इसमें निपटाए गए मामले किसी भी अदालत की जांच के अधीन नहीं थे। धारा 10(2) विधायिका की मंशा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि धारा 10(1) के तहत प्रकाशित उपधारा 8 और 9 के तहत आदेश को कानून के रूप में माना जाना था जिस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना था। ऐसे प्रावधान के पीछे बहुत अच्छा कारण था. यदि उपधारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेशों को अंतिम नहीं माना जाता, तो परिणाम यह होता कि कोई भी मतदाता, यदि चाहे तो, अदालत से अदालत तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठाकर अनिश्चित काल तक चुनाव रोक सकता है। [410 बी-सी, जी, एच]

हालाँकि धारा 10(1) के तहत प्रकाशित धारा 8 या धारा 9 के तहत कोई आदेश संसद के अधिनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव वही होगा। धारा 10(4) ऐसे आदेश को संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान स्थिति में रखती है जिसे केवल अनुच्छेद 327 के तहत ही बनाया जा सकता है। (415 ई)

संदर्भित मामला कानून।

अनुच्छेद 82 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर लोगों के सदन में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को फिर से समायोजित करना पड़ सकता है। यह अनुच्छेद 327 है जो संसद को समय-समय पर संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और ऐसे सदन के उचित संविधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का आदेश देता है। [406 सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 1966 की सिविल अपील सं. 843।

विविध याचिका क्रमांक 72 सन् 1965 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25 फरवरी 1965 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से जी. एन. दीक्षित, के. एल. मोरे और आर. एन.दीक्षित निरेन डे, एडिशनल।

सॉलिसिटर-जनरल आर. गणपति अय्यर और आर. एच. ढेबर और बी. आर. जी. के. आचार, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1-4।

एस. एस. शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश मित्तर द्वारा सुनाया गया।

यह 1965 की विविध याचिका संख्या 72 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 25 फरवरी, 1965 के फैसले और आदेश की विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जिसमें प्रार्थना की गई थी मध्य प्रदेश राज्य में कुछ संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की रिट। याचिका इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 329 (ए) के तहत उक्त अधिसूचना पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अनुच्छेद 329 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, पढ़ता है:

> "इस संविधान में कुछ भी होते हुए भी:
>
> (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद 327 के तहत बनाया गया है या बनाया जाना है। या अनुच्छेद 328, पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि जिस अधिसूचना का उल्लेख किया गया है वह कानून नहीं है और दूसरी बात यह कि यह संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत नहीं बनाई गई थी।

तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता उज्जैन का निवासी है और भारत का नागरिक है। वह पिछले सभी आम चुनावों में मतदाता रहे हैं और अभी भी उज्जैन की मतदाता सूची में दौलतगंज, वार्ड नंबर 5 में मतदाता होने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि उन्हें मध्य प्रदेश राज्य में किसी भी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार है। 24 जुलाई 1964 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित विवादित अधिसूचना में उज्जैन को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। यह परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में बनाया गया था और यह बताता है कि मध्य प्रदेश राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के प्रस्ताव 15 अक्टूबर 1963 को प्रकाशित किए गए थे। भारत के राजपत्र और मध्य प्रदेश राज्य के आधिकारिक राजपत्र में और सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने यह निर्धारित किया कि जिन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश राज्य को सदन के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित किया

जाएगा। ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनता और सीमा तालिका ए में दर्शाई गई होगी।

याचिका के प्रतिवादी क्रमांक 1 परिसीमन आयोग थे, प्रतिवादी क्रमांक 2 इसके अध्यक्ष और प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 इसके सदस्य थे। याचिका में आयोग और उसके अध्यक्ष की ओर से कई चूक और कमीशन का आरोप लगाया गया है, लेकिन हम यहां उन सब से चिंतित नहीं हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लेखित संक्षिप्त आधार पर याचिका को खारिज करना उचित नहीं था, तो हमें मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेजना होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, भारत के संविधान की शुरुआत से ही उज्जैन शहर एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र रहा है और शहर को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने से इस निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए उम्मीदवार होने का उनका अधिकार छीन लिया गया है।

परिसीमन आयोग के कामकाज की सराहना करने के लिए और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का संदर्भ दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि-

> "प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, राज्यों को लोक सभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और इस

तरह से पुनः समायोजित किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा कर सकती है।" निर्धारित करें।

परन्तु कि इस तरह का पुनर्समायोजन तत्कालीन मौजूदा सदन के विघटन तक लोगों के सदन में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा।"

यह अनुच्छेद 1956 में संशोधन से पहले संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) की एक शब्दशः प्रतिलिपि है।

संविधान के अनुच्छेद 327 में प्रावधान है कि- "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है।"या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं।

हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1962, अनुच्छेद 327 के तहत संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था, बल्कि अनुच्छेद 82 के तहत पारित किया गया था और इस तरह कानून की अदालतों को परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचना की वैधता के सवाल पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 329 के शुरुआती शब्दों के कारण। हालाँकि, अनुच्छेद 82 में

केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर लोगों के सदन में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को फिर से समायोजित करना पड़ सकता है। यह अनुच्छेद 327 है जो संसद को समय-समय पर संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और ऐसे सदन के उचित संविधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का आदेश देता है।

परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 की प्रस्तावना से पता चलता है कि यह राज्यों को लोक सभा में सीटों के आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, के विभाजन के पुनः समायोजन का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। प्रत्येक राज्य को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों के लिए और उनसे जुड़े मामलों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 82 केवल यह दर्शाता है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर पुनः समायोजन आवश्यक हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उससे जुड़े अन्य सभी मामलों के साथ-साथ संसद के किसी भी सदन के चुनाव सहित इस तरह के पुनः समायोजन के लिए विस्तृत प्रावधान करने की शक्ति देता है। परिसीमन आयोग अधिनियम (इसके बाद अधिनियम में संदर्भित) की धारा 3 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रारंभ

होने के बाद जितनी जल्दी हो सके एक आयोग का गठन करने का आदेश देती है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाएगा। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यह आयोग का कर्तव्य है कि वह नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कई राज्यों के लिए लोक सभा में सीटों के आवंटन और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करे। लोक सभा के लिए चुनाव। अधिनियम की धारा 8 आयोग के लिए नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा निर्धारित करना अनिवार्य बनाती है। प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाने वाली लोक सभा में सीटों की संख्या और राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो, साथ ही आवंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या प्रत्येक राज्य की विधान सभा और राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अधिनियम की धारा 9, उपधारा (1) में प्रदान किया गया है-

> "आयोग, यहां दिए गए तरीके से, प्रत्येक राज्य को आवंटित लोक सभा की सीटों और प्रत्येक राज्य की विधान सभा को सौंपी गई सीटों को एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन

क्षेत्रों में वितरित करेगा और नवीनतम जनगणना के आधार पर उनका परिसीमन करेगा। आंकड़े, संविधान के प्रावधानों और निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्:

(ए) सभी निर्वाचन क्षेत्र, जहां तक संभव हो, भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्र होंगे, और उनका परिसीमन करते समय भौतिक विशेषताओं, मौजूदा सीमाओं को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासनिक इकाइयाँ, संचार और सार्वजनिक सुविधा की सुविधाएँ;

(बी) प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि वह पूरी तरह से एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए;

(सी) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, उन क्षेत्रों में स्थित किया जाएगा, जहां कुल आबादी में उनकी आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से बड़ा है; और

(डी) निर्वाचन क्षेत्र जिनमें सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जहां तक संभव हो, उन क्षेत्रों में स्थित

होंगे जहां कुल आबादी में उनकी आबादी का अनुपात सबसे बड़ा है।"

अनुभाग की उपधारा (2) के तहत आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्तावों को किसी सहयोगी सदस्य के असहमतिपूर्ण प्रस्तावों, यदि कोई हो, के साथ प्रकाशित करेगा, एक तारीख निर्दिष्ट करेगा जिसके बाद या उसके बाद प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे प्राप्त हुए होंगे। इस प्रकार निर्दिष्ट दिन से पहले। इसके बाद इसका कर्तव्य एक या एक से अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को निर्धारित करना है। धारा 10 (1) के तहत आयोग के आदेशों को प्रचारित किया जाना है। अधिनियम। उपधारा (1) निर्धारित करती है कि धारा 8 या धारा 9 के तहत किए गए इसके प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबंधित राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित किया जाना है। उपधारा (3) में प्रावधान है कि ऐसे प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और संबंधित राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

आदेशों का कानूनी प्रभाव अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और (4) में दिया गया है। उपधारा (2) के तहत "भारत के राजपत्र में प्रकाशन पर, ऐसे प्रत्येक आदेश पर कानून का बल होगा और किसी भी

अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा"। उपधारा (4) के तहत (अप्रासंगिक भाग को छोड़कर) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन और ऐसे किसी भी आदेश में प्रदान किए गए उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन लागू होगा। सदन या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के संबंध में, जैसा भी मामला हो, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बाद आयोजित किया जाता है और यह प्रतिनिधित्व में निहित ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन से संबंधित प्रावधानों के अधिक्रमण में लागू होगा। लोक अधिनियम 1950, और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 1961।

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधायिका की मंशा थी कि प्रकाशन के बाद धारा 8 और 9 के तहत प्रत्येक आदेश को कानून की शक्ति प्राप्त हो और किसी भी अदालत में विवाद का विषय न बनाया जाए। दूसरे शब्दों में, संसद धारा 10(2) को अधिनियमित करके यह स्पष्ट करना चाहती थी कि धारा 8 और 9 के तहत पारित आदेशों को कानून की बाध्यकारी शक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल प्रशासनिक निर्देशों के रूप में। इसे धारा 10 की उपधारा (4) द्वारा और भी सुदृढ़ किया गया है जिसके अनुसार लोक सभा में कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन और उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे किसी भी आदेश में प्रदान किया गया है (अर्थात धारा 8 या धारा के तहत)

9) भारत के राजपत्र में आदेश के प्रकाशन के बाद होने वाले सदन के प्रत्येक चुनाव के संबंध में लागू होना था और आदेश में निहित ये प्रावधान लोगों के प्रतिनिधित्व में निहित ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन से संबंधित सभी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने वाले थे। अधिनियम, 1950 और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1961। वास्तव में, इसका मतलब इस प्रकृति के सभी प्रावधानों का पूर्ण उन्मूलन है जो धारा 8 और 9 के तहत आदेश पारित होने से पहले लागू थे और केवल ऐसे आदेश लागू थे। कायम रहना। इसलिए यद्यपि विवादित अधिसूचना संसद द्वारा पारित कोई क़ानून नहीं थी, यह संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित एक कानून था।

हमारा ध्यान राज्यों को लोक सभा में सीटों के आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए पुन: समायोजन प्रदान करने वाले विधेयक संख्या 98 या 1962 की ओर आकर्षित किया गया था। लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों के लिए और उनसे जुड़े मामलों और उनके उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए जैसा कि वर्ष 1962 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2 में दिखाई देता है जिसमें अनुच्छेद 82 का उल्लेख है और संविधान की धारा 170(3)। उक्त

कथन से यह भी पता चलता है कि चूंकि 1961 की जनगणना पूरी हो चुकी थी, इसलिए पहले उल्लेखित कई मामलों का पुन: समायोजन आवश्यक था क्योंकि 1951 की जनगणना से जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव आया था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि परिसीमन आयोग अधिनियम अनुच्छेद 82 के तहत बनाया गया एक कानून था। अनुच्छेद 82, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुन: समायोजन आवश्यक हो सकता है और इसे संसद द्वारा प्रभावी किया जाना चाहिए जैसा वह समझ सकती है। फिट है, लेकिन यह अनुच्छेद 327 है जो संसद पर विशेष रूप से यह कर्तव्य डालता है कि वह संसद के किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित सभी मामलों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उचित संविधान को सुरक्षित करने के लिए अन्य आवश्यक मामलों के संबंध में प्रावधान करे।

अधिनियम की धारा 10 (2) के संबंध में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 9 के तहत आदेश को कानून का बल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा आदेश स्वयं कानून नहीं है। इस विवाद का समर्थन करने के लिए हमारा ध्यान महामहिम राजा बनाम विलियम सिंगर(1) मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया गया। 1914 के युद्ध उपाय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि इस धारा के तहत बनाए गए सभी आदेशों

और विनियमों में कानून का बल होगा और उन्हें इस तरह से और राज्यपाल जैसे न्यायालयों, अधिकारियों और प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जाएगा। परिषद् निर्धारित कर सकती है और किसी भी बाद के आदेश या विनियम द्वारा इसमें परिवर्तन, विस्तार या निरस्त किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 के द्वारा गवर्नर-इन-काउंसिल को इस अधिनियम के तहत आदेशों और विनियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले दंडों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था और यह भी निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसे दंड संक्षिप्त दोषसिद्धि पर या अभियोग पर लगाए जाएंगे। युद्ध उपाय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए गवर्नर-इन-काउंसिल ने इस आशय का आदेश दिया कि कोई भी खुदरा दवा विक्रेता सीधे कोडीन की बिक्री या आपूर्ति नहीं करेगा, चाहे पाउडर, टैबलेट या तरल रूप में, या किसी भी मात्रा में युक्त तैयारी। ओपियम और नारकोटिक ड्रग अधिनियम की अनुसूची के भाग । और ॥ में उल्लिखित नशीली दवाओं को औषधीय या अन्य अवयवों के साथ मिलाया जाता है, सिवाय किसी चिकित्सक, पशु चिकित्सा सर्जन या दंत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित लिखित आदेश या नुस्खे के... .आदेश में आगे प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोडीन या ओपियम और नारकोटिक ड्रग अधिनियम की अनुसूची के भाग । और ॥ में उल्लिखित नशीली दवाओं को अन्य औषधीय या अन्य अवयवों के साथ मिश्रित नशीली दवाओं के कब्जे में पाया जाता है, सिवाय इसके कि किसी

के अधिकार के तहत। पेंशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति, अफीम और नारकोटिक ड्रग अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत संक्षिप्त दोषसिद्धि पर प्रदान किए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

ओपियम और नारकोटिक ड्रग अधिनियम, जो एक डोमिनियन क़ानून था, में एक अनुसूची शामिल थी जिसमें नशीली दवाओं की गणना की गई थी, लेकिन जिसमें विचाराधीन आदेश की तारीख तक कोडीन शामिल नहीं था। उस आदेश के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी, एक खुदरा दवा विक्रेता के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने बिना किसी वैध कारण के कनाडा की संसद के एक अधिनियम की अवज्ञा की, जिसके लिए कोई जुर्माना या सजा का अन्य तरीका स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया था; युद्ध उपाय अधिनियम के सितंबर, 1939 के 11 वें दिन के विनियमों के पैराग्राफ दो में, ओपियम और नारकोटिक ड्रग अधिनियम की अनुसूची के भाग दो में उल्लिखित एक मादक दवा कोडीन को जानबूझकर बिना लिखित आदेश प्राप्त किए या प्राप्त किए बिना बेचकर। इसके लिए डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित नुस्खा धारा 164, कनाडा की आपराधिक संहिता के विपरीत है। आपराधिक संहिता की धारा 164 में विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है कि अपराध में जानबूझकर कोई भी कार्य करना शामिल होना चाहिए जो कि निषिद्ध था या किसी भी कार्य को करने

से चूकना जो कि कनाडा की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाना आवश्यक था। जज रिनफ्रेट ने अपने फैसले में कहा: (पेज .114) :-

> "यह कनाडा की संसद का एक अधिनियम है जिसे दोषी व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी बहाने के अवज्ञा किया होगा।"

न्यायाधिपति,ट्रायल जज और अपील न्यायालय के बहुमत से सहमत था कि परिसर में आपराधिक संहिता की धारा 164 का कोई अनुप्रयोग नहीं था और कहा: - "बेशक, युद्ध उपाय अधिनियम अधिनियमित करता है कि इसके तहत बनाए गए आदेश और नियम "कानून का बल होगा. यह अन्यथा नहीं हो सकता. उनका पालन कराया जाता है और परिणामस्वरूप, उनके पास कानून का बल होना चाहिए। लेकिन यह कहने से बिल्कुल अलग बात है कि उन्हें संसद का अधिनियम माना जाएगा।"

तशरेउ न्यायाधीश ने मामले को संक्षिप्त रूप से रखा (पेज 124 पर देखें)

> "परिषद में एक आदेश कार्यकारी परिषद द्वारा पारित किया जाता है, और संसद का एक अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स और कनाडा की सीनेट द्वारा अधिनियमित किया जाता है। दोनों पूरी तरह से अलग हैं, और जब तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि परिषद में आदेशों को

कानून का हिस्सा माना जाएगा, या कि नियमों के खिलाफ कोई भी अपराध अधिनियम का उल्लंघन होगा, तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि परिषद में एक आदेश का उल्लंघन आपराधिक संहिता की धारा 164 के अर्थ के भीतर संसद के एक अधिनियम का उल्लंघन है।"

न्यायाधीश ताशेरेउ के फैसले की टिप्पणियाँ उन चीज़ों के बीच अंतर को इंगित करती हैं जिनमें कानून का बल है संसद के एक अधिनियम से अलग। कनाडाई मामले में काउंसिल में आदेश, हालांकि इसमें कानून का बल था, संसद के अधिनियम में निहित कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए हालांकि परिषद में आदेश का उल्लंघन था, लेकिन कनाडा डोमिनियन की संसद के अधिनियम के किसी भी खंड का उल्लंघन का कोई प्रावधान नहीं था।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा, भूरे लाल बया (1) में इस न्यायालय के फैसले पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम एक्सएल III) की धारा 105 के प्रभाव पर विचार करने के लिए जिसमें प्रावधान है कि "इस अधिनियम के तहत दिया गया ट्रिब्यूनल का हर आदेश अंतिम और निर्णायक होगा"। वहां तर्क यह दिया गया कि यह प्रावधान न्यायाधिकरण के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

उच्च न्यायालय या उसकी अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न से परे रखता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विधानमंडल का इरादा यह था कि न्यायाधिकरणों के निर्णय सभी मामलों पर अंतिम हों, चाहे वे तथ्य के हों या कानून के, और यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने दायरे में कार्य करते समय कानून की त्रुटि करते हैं। उन्होंने तय किया कि कानून क्या है. इस दलील को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और हरि विष्णु बनाम अहमद शेख (2) का संदर्भ देने के बाद यह देखा गया था कि "न्यायालय ने सामान्य शब्दों में कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इस पर सीमाएं नहीं लगाई जा सकतीं।"यह, स्वयं संविधान को छोड़कर।"

इस मामले में हमें उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि संविधान स्वयं अनुच्छेद 329 (ए) के तहत प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 327 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि से संबंधित या बनाए जाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसलिए धारा 8 या 9 के तहत एक आदेश और धारा 10(1) के तहत प्रकाशित केवल अभिव्यक्ति के उपयोग के कारण बचाया नहीं जा सकेगा, किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"लेकिन अगर राजपत्र में आदेश के प्रकाशन से भारत में इसे

अनुच्छेद 327 के तहत बनाया गया कानून माना जाएगा, अनुच्छेद 329 किसी भी अदालत द्वारा किसी भी जांच को रोक देगा।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को खारिज करने में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया एन.पी. पुन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य (1) में, जो कुछ रियायतों के आधार पर आगे बढ़ा। वहां अपीलकर्ता एक व्यक्ति था जिसने नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र से मद्रास विधान सभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसके नामांकन पत्र को खारिज करने के आदेश को रद्द करने और उक्त अधिकारी को वैध नामांकन की सूची में उसका नाम शामिल करने का निर्देश देने के लिए सर्टिओराय की रिट की प्रार्थना की। प्रकाशित. उच्च न्यायालय ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के कारण रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने बताया (पेज 225 पर):-

"एक ओर अनुच्छेद 327 और 328 और दूसरी ओर अनुच्छेद 329 में प्रयुक्त भाषा में एक उल्लेखनीय अंतर यह

है कि जहां पहले दो अनुच्छेद "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन"शब्दों से शुरू होते हैं, वहीं अंतिम अनुच्छेद "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन"शब्दों से शुरू होता है। शब्द "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी"। बार में यह माना गया कि भाषा में इस अंतर का प्रभाव यह है कि जबकि संसद द्वारा अनुच्छेद 327 के तहत, या राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 328 के तहत बनाया गया कोई भी कानून, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 329 में दिए गए मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है।"

अधिवक्ता द्वारा कुछ अन्य रियायतों का भी संदर्भ दिया गया था जो रिपोर्ट के पीपी 233 और 237 में दिखाई देती हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाएगा कि उस मामले में निर्णय नहीं हुआ था। दी गई रियायतों पर आगे न बढ़ें। न्यायालय ने संविधान के भाग XV और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की योजना की कुछ हद तक जांच की, जिसे संसद ने संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत सभी के संबंध में विस्तृत प्रावधान बनाने के लिए पारित किया था। देश में विभिन्न विधानमंडलों के चुनावों से जुड़े मामले और सभी चरण। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम संविधान के प्रावधानों के अधीन अधिनियमित किया गया था, इसलिए यह रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया: -

> "हालाँकि, अनुच्छेद 329 (बी) के साथ अधिनियम को पढ़ने पर यह तर्क पूरी तरह से खारिज हो जाता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि उस अनुच्छेद में और अधिनियम की धारा 80 में किस भाषा का उपयोग किया गया है लगभग समान है, केवल इस अंतर के साथ कि अनुच्छेद के पहले "इस संविधान में कुछ भी होते हुए भी"शब्द हैं। (पृष्ठ 232)

न्यायालय ने पृष्ठ 233 पर टिप्पणी की:-

> "यह बताया जा सकता है कि अनुच्छेद 329 (बी) को उस अनुच्छेद के खंड (ए) के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। खंड (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुच्छेद 327 और 328 के तहत बनाए गए ऐसे कानून के संबंध में अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है। संविधान का भाग चुनाव प्रक्रिया के एक भाग को उच्च न्यायालयों के

समक्ष प्रतियोगिता का विषय बनाया जाएगा और इस प्रकार चुनाव की समय-सारिणी को बिगाड़ दिया जाएगा। अधिक उचित दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 329 सभी "चुनावी मामलों"को शामिल करता है।

अधिनियम की उपधारा 8 और 9 की जांच से पता चलता है कि इसमें निपटाए गए मामले किसी भी अदालत की जांच के अधीन नहीं थे। धारा 8, जो सीटों की संख्या के पुनर्समायोजन से संबंधित है, दर्शाती है कि आयोग को नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा संख्या निर्धारित करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य को लोक सभा में आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या और राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो। इसी प्रकार, धारा 9 के तहत आयोग का यह कर्तव्य था कि वह प्रत्येक राज्य को आवंटित लोक सभा की सीटों और प्रत्येक राज्य की विधान सभा को सौंपी गई सीटों को एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित करे और आधार के आधार पर उनका परिसीमन करे। संविधान के प्रावधानों और उपधारा (1) के खंड (ए) से (डी) में गिनाए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए नवीनतम जनगणना के आंकड़े। धारा 9 की उपधारा (2) से पता चलता है कि उपधारा (1) के तहत किया

गया कार्य अंतिम नहीं था, लेकिन आयोग (ए) को असहमति वाले प्रस्तावों के साथ उपधारा (1) के तहत अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करना था, यदि किसी भी सहयोगी सदस्य को, (बी) एक तारीख निर्दिष्ट करने के लिए जिसके बाद प्रस्तावों पर आगे विचार किया जा सके, (सी) उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए जो इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त हुए हों, और इस उद्देश्य के लिए इस तरह के विचार, ऐसे स्थान या स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए जैसा वह उचित समझे। ऐसा तभी होता है जब आयोग एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित कर सकता है।

इसलिए, हमारे विचार में, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आपत्ति पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि से पहले ही विचार किया जा सकता है। एक बार जब आयोग द्वारा उपधारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेश भारत के राजपत्र और संबंधित राज्यों के आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित हो गए, तो इन मामलों को अदालत में दोबारा नहीं उठाया जा सकता था। ऐसे प्रावधान के पीछे बहुत अच्छा कारण प्रतीत होता है। यदि उपधारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेशों को अंतिम नहीं माना जाएगा, तो इसका प्रभाव यह होगा कि कोई भी मतदाता, यदि चाहे तो, अदालत से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठाकर अनिश्चित काल के लिए चुनाव रोक

सकता है। अधिनियम की धारा 10(2) विधानमंडल की मंशा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि धारा 10(1) के तहत प्रकाशित धारा 8 और 9 के तहत आदेशों को कानून के रूप में माना जाना था जिस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना था।

यह सच है कि धारा 10(1) के तहत प्रकाशित धारा 8 या 9 के तहत कोई आदेश संसद के अधिनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव वही होना है।

यहां की स्थिति कुछ हद तक हरिशंकर बागला और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में प्राप्त की गई तुलना से मेल खाती है। (1) आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, जहां तक ऐसा प्रतीत होता है किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, या उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन बनाने के लिए, आदेश द्वारा इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया जा सकता है। धारा 4 के तहत अधिसूचित आदेश द्वारा केंद्र सरकार के लिए यह निर्देश देना खुला था कि धारा 3 के तहत आदेश देने की शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रयोग योग्य होगी। केंद्र

सरकार या ऐसी राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है:-

धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को प्रख्यापित किया , 1948, सूती कपड़ा (आंदोलन पर नियंत्रण) आदेश, 1948। उक्त आदेश की धारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति रेल, सड़क, वायु, समुद्र या अंतर्देशीय नेविगेशन द्वारा किसी भी कपड़े, धागे या परिधान का परिवहन या परिवहन नहीं करेगा, सिवाय इसके कि और कपड़ा आयुक्त द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित एक सामान्य परमिट या कपड़ा आयुक्त द्वारा जारी एक विशेष परिवहन परमिट के अनुसार। अपीलकर्ता हरिशंकर बागला और उनकी पत्नी को धारा 7 के उल्लंघन के लिए रेलवे पुलिस द्वारा इटारसी में गिरफ्तार किया गया था। सूती कपड़ा (आंदोलन पर नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड (3) के साथ पठित आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 के तहत छह मन से अधिक वजन का नया सूती कपड़ा पाया गया, जिसे वे बंबई से ले जा रहे थे। बिना किसी परमिट के कानपुर. मध्य प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि अधिनियम की

धारा 6 असंवैधानिक है, उचित नहीं था। इस तर्क को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया और इसका अवलोकन किया गया:-

> "धारा 6 को अधिनियमित करके संसद ने स्वयं घोषित किया है कि धारा 3 के तहत दिया गया आदेश इस अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम के साथ इस आदेश में किसी भी असंगतता के बावजूद प्रभावी होगा। यह प्रतिनिधि द्वारा की गई घोषणा नहीं है बल्कि विधायिका ने स्वयं धारा 6 में अपनी इच्छा की घोषणा की है। प्रतिनिधि की शक्ति केवल धारा 3 के तहत आदेश देने की है। एक बार जब प्रतिनिधि ने वह आदेश दे दिया तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। धारा 6 में वह कदम है जिसमें संसद ने घोषणा की है कि जैसे ही ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में आएगा, इस अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम में निहित किसी भी असंगतता के बावजूद वह प्रभावी होगा।"

इसी प्रकार यहां यह कहा जा सकता है कि एक बार जब परिसीमन आयोग ने उपधारा 8 और 9 के तहत आदेश दिए हैं और उन्हें धारा 10(1) के तहत प्रकाशित किया गया है, तो आदेशों का वही प्रभाव होगा जैसे कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून हों।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कैलाश नाथ और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। और दूसरे। वहीं धारा 4 के तहत उ.प्र. बिक्री कर अधिनियम में राज्य सरकार को या तो कुछ प्रकार के लेनदेन को बिक्री कर के भुगतान से पूरी तरह छूट देने या देय कर के एक हिस्से की छूट की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था। इसके अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि 1 दिसंबर, 1949 से अधिनियम की धारा 3 (बिक्री कर लगाने से संबंधित) के प्रावधान सूती कपड़े या धागे की बिक्री पर लागू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश, 1 दिसंबर, 1949 को या उसके बाद भारत के क्षेत्रों के बाहर ऐसे कपड़े या धागे को निर्यात करने की दृष्टि से बनाया गया था, इस शर्त पर कि कपड़ा या धागा वास्तव में निर्यात किया गया है और ऐसे वास्तविक निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि "यह अधिसूचना क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार बनाई गई है, इसमें वैधानिक बल और वैधता है और इसलिए, छूट ऐसी है जैसे कि यह मूल अधिनियम में ही निहित है।"

जयंतीलाल अमृत लाल स्लवधन बनाम एफ एन राणा और अन्य (2) में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना का प्रभाव था। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत 24 जुलाई 1959 को

एक अधिसूचना द्वारा बॉम्बे सरकार की सहमति से बॉम्बे राज्य में डिवीजनों के आयुक्तों को केंद्र सरकार के कार्यों के संबंध में सौंपा। संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम (1960 का XI) द्वारा दो नए राज्यों का गठन किया गया और बड़ौदा डिवीजन को गुजरात राज्य को आवंटित किया गया। 24 जुलाई, 1959 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा डिवीजन के आयुक्त ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) की धारा 4 {1) के तहत अपीलकर्ता की भूमि को जनता के लिए आवश्यक होने के रूप में अधिसूचित किया। उद्देश्य, और अधिनियम के तहत कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अहमदाबाद को अधिकृत किया। विशेष अधिग्रहण अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद यह रिपोर्ट आयुक्त को सौंपी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एक घोषणा जारी की। इसके बाद अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। उनका मामला अन्य बातों के अलावा यह था कि अनुच्छेद 258 (1) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना विभाजन के बाद अप्रभावी थी क्योंकि नवगठित राज्य गुजरात की सरकार से अपने अधिकारी को कार्य सौंपने की सहमति अनुच्छेद 258 के अनुसार प्राप्त नहीं की गई थी। (1).

संविधान के अनुच्छेद 258 (1) में लिखा है: -

"इस संविधान में किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस सरकार या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकता है।"जिसका विस्तार संघ की कार्यकारी शक्ति करती है।"

इस न्यायालय के समक्ष रखे गए तर्कों में से एक यह था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रकृति में कार्यकारी थी और अनुच्छेद 258(1) के तहत राज्य सरकार को जो कार्य सौंपे जा सकते थे, वे कार्यकारी थे और इस प्रकार ऐसे कार्यकारी प्राधिकार को सौंपा जाना उचित नहीं था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के अर्थ में कानून, जिसने नियत दिन के बाद भी कानूनों की क्षेत्रीय सीमा को बनाए रखने के प्रावधान किए। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि 1 मई, 1960 के बाद नए राज्य गुजरात के आयुक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संघ के कार्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर अक्षम थे।

इस न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों द्वारा पृष्ठ 308 पर यह देखा गया: -

"जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (डी) के साथ पढ़ी गई धारा 87 के अर्थ में कानून है , 1960 का 11।"

केंद्र सरकार के कार्यों के अंतिम कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के तीन चरणों का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने कहा (पृष्ठ 309 पर):-

"अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और संविधान के अनुसार सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा सकता है और अनुच्छेद 73 द्वारा संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन विस्तारित है। :

(ए) उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और

(बी) ऐसे अधिकारों, अधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए जो किसी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं:

परन्तु कि उप खंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, संविधान में या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए शक्ति को छोड़कर, किसी भी राज्य में उन मामलों तक विस्तारित नहीं

होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। प्रथम दृष्टया, संघ की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित है जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में संसद की शक्ति का विस्तार है।

न्यायालय ने तब अनुच्छेद 258(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति पर विचार किया। यह नोट किया गया कि आइटम 42 सूची III द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का विषय समवर्ती सूची में आता है और संघ की संसद को संघ के उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है और अनुच्छेद 73(1)(ए) द्वारा संघ की कार्यकारी शक्ति को बढ़ा दिया गया है। संघ के लिए संपत्ति का अधिग्रहण. यह देखा गया कि "संविधान के अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने तक विस्तारित है। अभिव्यक्ति "अधिग्रहण"हमारे निर्णय में, संपत्ति का धारण और निपटान"में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण शामिल होगा। यह संविधान में एक प्रावधान है जो अनुच्छेद 73 (1) के प्रावधानों के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि संसद संघ के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और परिणामस्वरूप, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण

के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति बच जाती है, जिससे राज्य की भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति बच जाती है.

न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य(1) के मामले का भी संदर्भ दिया गया था, जहां यह माना गया था कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 94(3) के तहत एक आदेश दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के निरसन के बावजूद, कानून लागू है। अंत में, न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा यह माना गया (पृष्ठ 315):-

> "हमें एडवर्ड मिल्स मामले में गवर्नर जनरल द्वारा जारी की गई अधिसूचना और इस मामले में जिस अधिसूचना से हम निपट रहे हैं, उसके बीच सैद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं दिखता है।" . इसका मतलब यह नहीं है कि कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश में कानून की शक्ति होती है। यदि आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक है, या किसी वैधानिक प्राधिकार के प्रयोग में जारी नहीं किया गया है तो इसमें कानून की शक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जहां एक सामान्य आदेश एक कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा भी जारी किया जाता है जो एक क़ानून के तहत प्रयोग करने योग्य शक्ति प्रदान करता है, और जो इस प्रकार क़ानून को

संशोधित या जोड़ता है, ऐसी शक्तियों के प्रदान को कानून की शक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।"

इस मामले में यह माना जाना चाहिए कि परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित उपधारा 8 और 9 के तहत नियमों का एक पूरा सेट बनाना था जो सीटों की संख्या के पुनः समायोजन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को नियंत्रित करेगा।

इस मामले में परिसीमन आयोग अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियां और आयोग का काम पूरी तरह से निरर्थक होगा जब तक कि आयोग अपने विचार-विमर्श और सार्वजनिक बैठकों के परिणामस्वरूप लोगों के सदन में सीटों की संख्या को फिर से समायोजित करने की स्थिति में न हो या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के साथ विधान सभा को सौंपी जाने वाली सीटों की कुल संख्या। यह संसद की इच्छा थी कि आयोग आदेश द्वारा अपने प्रस्तावों को प्रकाशित कर सकता था जिन्हें बाद के चुनाव में प्रभावी किया जाना था और इस तरह उसके आदेश को भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र की अधिसूचना में प्रकाशित किया जाना था। इस विषय पर कानून के रूप में माना जाता है।

मौजूदा मामले में अधिनियम की धारा 10 (4) का प्रावधान धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित उपधारा 8 और 9 के तहत आदेशों को संसद द्वारा

बनाए गए कानून के समान रखता है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। केवल अनुच्छेद 327 के तहत ही किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप यह आपत्ति कि अधिसूचना को कानून नहीं माना जाना चाहिए, को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और जुर्माने सहित खारिज कर दी जाती है।

आर.के.पी.एस.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुखराज गहलोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।